

संक्षिप्त खबरें

जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पास किया

रांची में 2029 तक आईटी पार्क शुरू करने की तैयारी, पहले चरण में 20 हजार रोजगार का लक्ष्य

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने सोमवार को एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें भारत सरकार से जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई है। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को पेश किया था। प्रस्ताव में कहा गया है कि सदन भारत सरकार से जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की जाती है, ताकि इसे भारत सरकार को भेजा जा सके। जब प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी, तो भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। दिन का तय कामकाज पूरा होने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और अब सदन की बैठक मंगलवार को होगी।

एससी से हरी झंडी : 2000 से ऊपर के यूपीआई पेंमेंट पर लगेगा चार्ज

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 2,000 रुपये से अधिक के निर्धारित यूपीआई व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन पर 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' (एमडीआर) लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केन्द्र और अन्य से सोमवार को जवाब मांगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए प्रहाराय को उद्घाटन करते हुए शाह ने कहा कि आतंकवाद-रोधी ढांचे के हर स्तर पर स्वाचित प्रतिक्रिया प्रणाली को संस्थागत बनाने और

बिभा संवाददाता रांची। ककि रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आरएमजे इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रेसिडेंट दीपक खबडिया ने मुलाकात की। इस दौरान झारखंड में अत्याधुनिक आईटी पार्क विकसित करने, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) स्थापित करने तथा तकनीकी एवं औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर एनर्जी और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विचार किया गया। प्रस्तावित योजना के तहत वर्ष

2029 तक रांची में आईटी पार्क शुरू करने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके पहले चरण में करीब 20 हजार रोजगार के अवसर सृजित करने और अगले तीन वर्षों में इसकी क्षमता बढ़ाकर लगभग 75 हजार रोजगार अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्य के स्थानीय और प्रतिभाशाली युवाओं को तकनीकी तथा उच्च-कौशल आधारित रोजगार के नए अवसर मिलने की संभावना है। प्रस्तावित आईटी पार्क के लिए आईआईएम रांची, नए विधानसभा परिसर और उच्च न्यायालय परिसर के निकट उपलब्ध करीब 100 एकड़ भूमि को संभावित स्थल के रूप में विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। पार्क में आधुनिक



कार्यालय, डिजिटल अधोसंरचना और वैश्विक स्तर की तकनीकी कंपनियों एवं संस्थानों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित करने की परिकल्पना है। इसका उद्देश्य रांची को आईटी, इनोवेशन और हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है। बैठक में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना की संभावनाओं पर भी

के विस्तार को गति मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड को भविष्य की तकनीकों और नई औद्योगिक संभावनाओं से जोड़ने हुए मजबूत एवं आधुनिक आईटी तथा तकनीकी इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। निवेश आकर्षित करने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और उच्च-कौशल आधारित अवसरों का सृजन सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची को आईटी, इनोवेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। राज्य में उपलब्ध प्रतिभाशाली मानव

संसाधन और विकास की संभावनाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर झारखंड को नई अर्थव्यवस्था के अनुरूप तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर संभावित रूप से अक्टूबर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल बंगलुरु का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल वहां विकसित आईटी पार्क, तकनीकी इकोसिस्टम और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर मॉडल का अध्ययन करेगा। इसके अलावा आईटी अधोसंरचना, निवेश व्यवस्था और उद्योगों को उपलब्ध सुविधाओं का भी अवलोकन किया जाएगा। इस अध्ययन के आधार पर झारखंड में आईटी पार्क और संबंधित तकनीकी इकोसिस्टम के

विकास के लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने में मदद मिलेगी। आरएमजे इन्फ्रास्ट्रक्चर की ओर से झारखंड में अत्याधुनिक आईटी पार्क, डिजिटल अधोसंरचना और भविष्य की तकनीकों से जुड़े क्षेत्रों में रुचि व्यक्त की गई। बैठक में राज्य में तकनीकी एवं औद्योगिक निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों तथा संभावित सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार-विमर्श हुआ। बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की सचिव पूजा सिंचल और झारखंड स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर (जेएसएसी) की निदेशक माधवी मिश्रा उपस्थित रहीं।

रांची टी 20: सबसे सस्ता 1600 और सबसे महंगा टिकट 18 हजार का

बिभा संवाददाता रांची : झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) ने रांची के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आगामी 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले टी-20 मैच के लिए टिकटों की दरों की घोषणा कर दी है। इस बार क्रिकेट प्रेमियों को मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए अधिक जेब ढीली करनी होगी, क्योंकि रांची में आयोजित अब तक के सभी अंतरराष्ट्रीय मैचों की तुलना में इस बार का टिकट दर सबसे महंगा रखा गया है। प्रबंधन की ओर से जारी दरों के तहत सबसे किफायती टिकट 1,600 रुपये का रखा गया है, जो स्टेडियम के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर स्थित हिल एरिया के लिए मान्य होगा। इस जगह दर्शक खुले मैदान

में घास पर बैठकर मैच का आनंद ले सकेंगे, जहां उनकी सुविधा के लिए बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगाई जाती हैं। वहीं, सबसे महंगी श्रेणी प्रेसिडेंट एनक्लोजर की है, जिसके एक टिकट की कीमत 18,000 रुपये तय की गई है। इस प्रीमियम श्रेणी के टिकट में विशेष हॉस्पिटैलिटी की सुविधाएं शामिल रहेंगी। इसके अतिरिक्त अन्य श्रेणियों में भी हॉस्पिटैलिटी सुविधाओं के साथ टिकट उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें कॉर्पोरेट बॉक्स का टिकट 8,000 रुपये, हॉस्पिटैलिटी बॉक्स 9,000 रुपये, लक्जरी पाल्स 10,000 रुपये और कॉर्पोरेट लाउंज का टिकट 15,000 रुपये निर्धारित किया गया है। टिकटों की बिक्री स्टेडियम के वेस्ट गेट की ओर बने विशेष काउंटर्स से की जाएगी।

प्रहार को थाना स्तर तक पहुंचाएं, अगले 10 साल के लिए मजबूत आतंकवाद-रोधी तंत्र बनाएं : शाह

एजेंसी नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को आतंकवाद-रोधी रणनीति ह्यप्रहारह् को थाना स्तर तक पहुंचाने और आतंकवादी घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर अगले 10 वर्षों के लिए एक मजबूत एवं ठोस तंत्र विकसित करने पर जोर दिया।



कार्रवाई में किसी भी तरह की देरी रोकने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है। प्रहार भारत की राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और

एजेंसियों की क्षमताओं को एकजुट करने तथा आतंकवाद के वित्तपोषण, हथियारों और सुरक्षित ठिकानों तक आतंकवादियों की पहुंच रोकने के लिए एक समन्वित व्यवस्था तैयार करना है। इस रणनीति के सात प्रमुख स्तंभों में शोकात्मक, प्रतिक्रिया, आंतरिक क्षमताओं को एकजुट करना, मानवाधिकार एवं कानून का शासन, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों को कम करना, अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के साथ तालमेल तथा पूरे समाज की भागीदारी के साथ पुनर्बहाली और लचीलापन शामिल हैं।

शाह ने कहा कि प्रहार के प्रत्येक स्तंभ पर परिणामोमुखी तरीके से काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई है। गृह मंत्री ने इस अवसर पर नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। उन्होंने कहा कि इससे विदेश में मौजूद भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय बेहतर होगा और प्रक्रिया में तेजी आएगी।

शेष पेज 11 पर

बड़गाई जमीन फर्जीवाड़ा: सीएम सोरेन ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका

बिभा संवाददाता रांची। बड़गाई की 8.86 एकड़ कथित जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय में उनके वकील ने याचिका दायर कर आरोप गठन की कार्यवाही रोकने की मांग की है। इसमें पीएमएलए के एक सेक्शन का हवाला देते हुए कहा गया है कि जब तक मामले में अनुसंधान पूरा नहीं होता है तब तक उनके खिलाफ आरोप गठन न किया जाए। अभी इस मामले में जांच पूरा नहीं हुआ है। याचिका में मुख्यमंत्री की ओर से पीएमएलए कानून के सेक्शन-44 के क्लॉज 01 के अंतर्गत सब क्लॉज-डी की संवैधानिक वैधता



को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि सेक्शन 44 के तहत स्पेशल कोर्ट पीएमएलए में आरोपित के खिलाफ ट्रायल उसी तरह चलना चाहिए जैसा सेशन कोर्ट में चलता है। उल्लेखनीय है कि मामले में मुख्यमंत्री की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन के खिलाफ याचिका की सुनवाई के दौरान झारखंड उच्च

अंतरराज्यीय बच्चा चोर गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार

बिभा संवाददाता रांची। रांची पुलिस ने रेलवे स्टेशन से बच्चा अपहरण मामले में अंतरराज्यीय बच्चा चोर गिरोह का खुलासा किया है। रांची पुलिस की एसआईटी ने अपहृत चार वर्षीय बालक विवान कुमार को साहेबगंज से सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड रोहित मुखर्जी उर्फ डॉन सहित पांच अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जबकि एक किशोर को निरुद्ध किया गया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से पांच मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। इस मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि बीते 24 सितंबर 2026 को रांची रेलवे स्टेशन के बाहर से विवान कुमार का अपहरण कर



लिया गया था। इस संबंध में चूटिया थाने में कांड संख्या-138/26 (धारा 137(2) बीएनएस) दर्ज की गई थी। मामले को सीबेदनशीलता को देखते हुए रांची एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर एक एसआईटी का गठन किया गया। टेक्निकल सेल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एसआईटी ने 27 सितंबर को

तीनपहाड़ स्थित बिट्टू के नानी घर पर छापेमारी कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस अनुसंधान में इस गिरोह के एक बेहद चौकाने वाले तौर-तरीके का पदार्फाश हुआ है। गिरोह का मुख्य सरगना रोहित मुखर्जी उर्फ डॉन चोरी के मामलों में जेल गए बच्चों को जमानत दिलाने में मदद करता था। इसके बाद वह इन लावारिस और असहाय बच्चों को अपने गिरोह में शामिल कर लेता था। इन बच्चों से देश के अलग-अलग शहरों के भीड़भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल चोरी करवाई जाती थी। चोरी के इन मोबाइलों को अवैध रूप से बांग्लादेश भेजकर खपाया जाता था। पुलिस इस गिरोह के नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों और बांग्लादेशी कनेक्शन को लेकर आगे की जांच और सघन पूछताछ कर रही है।

बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दिया इस्तीफा

एजेंसी पटना। बिहार विधान परिषद के सभापति और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अवधेश नारायण सिंह ने सोमवार देर शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद उपसभापति और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के विधान पार्षद रामवचन राय ने कार्यकारी सभापति के रूप में जिम्मेदारी संभाल ली। पद छोड़ने के बाद अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि उन्हें पार्टी का फैसला स्वीकार है और उन्हें किसी तरह का गिला-शिकवा नहीं है। पार्टी ने उन्हें चार बार विधान परिषद का सभापति बनने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि आगे पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उसका वे निर्वहन करेंगे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विधान



परिषद के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग के लिए आभारी जाताया। अवधेश नारायण सिंह के इस्तीफे के तुरंत बाद रामवचन राय ने कार्यकारी सभापति का पद संभाला। उन्होंने अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि वे मिली जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। रामवचन राय लंबे समय से बिहार विधान परिषद से जुड़े हैं और वर्तमान में जदयू के विधान पार्षद हैं। उनका मौजूदा विधान परिषद कार्यकाल 16 मार्च 2027 तक है।

नाबालिगों के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को मानना होगा भारतीय कानून, केन्द्र नियमों पर करे विचार: सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से इस संभावना पर विचार करने को कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य डिजिटल मध्यस्थों के लिए ऐसे वैधानिक नियम बनाए जाएं, जिनके तहत उन्हें नाबालिगों से संबंधित भारतीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य हो। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ स्वतंत्र रूप से अनुबंध करने के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा का पालन सुनिश्चित करना भी शामिल है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह दिप्पणी जस्टिस राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस (जेआरसीए) की ओर से



दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की। पीठ में अन्य दो जस्टिस न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे। याचिका में सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

मध्यस्थता नियमों के तहत ऐसे निर्देश जारी करें कि वे अपने सॉफ्टवेयर या जिस भी रूप में उस प्लेटफॉर्म को संचालित करते हैं, उसे भारतीय कानून के अनुरूप तैयार करें। सॉफ्टवेयर को भारतीय कानून के अनुरूप होना ही चाहिए। तुषार मेहता ने जवाब दिया, सरकार इस मुद्दे की जांच करेगी और जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा, कुछ किया जा सकता है, कुछ किया जाना चाहिए और किया जाएगा। मेहता ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत इंटरमीडियरी से संबंधित प्रावधानों का भी उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस बात

को लेकर चिंता जताई गई है कि नाबालिगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र रूप से अकाउंट बनाने और संचालित करने की अनुमति दी जा रही है, जबकि कानून वो किसी तरह का अनुबंध नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिका में उठाया गया मुद्दा प्रथम दृष्टया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के दायरे में आता है। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस कानून के संबंधित प्रावधान 2027 में ही लागू होंगे और इसलिए तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फुल्का ने कहा

शेष पेज 11 पर

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अविलम्ब त्यागपत्र दे : राजीव रंजन प्रसाद

ज्ञानेश कुमार पर उठे आरोपों की निष्पक्ष जांच हो : जय प्रकाश भाई पटेल

बिभा संवाददाता

हजारीबाग : जिला कांग्रेस कमिटी के तत्वावधान में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित और कांग्रेस की मांगों तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा वोटों की चोरी के विरोध डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक स्थित डॉ.भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रतिमा स्थल से चलकर नया समाहरणालय गेट के बाहर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व मंत्री सह जिला अध्यक्ष जय प्रकाश भाई पटेल ने किया। विरोध मार्च में अपने संबोधन में प्रदेश महासचिव



सह हजारीबाग जिला प्रभारी राजीव रंजन प्रसाद ने कहा की वोट भारतीय लोकतंत्र की नींव है। वोट से ही हमारे संविधान को ताकत, हमारे कानूनों को अधिकार और हमारे सार्वजनिक संस्थानों को वैधता मिलती है - यही कड़ी आधुनिक भारत की पहचान है। आज यह कड़ी टूट गई है, और

भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वोट को खत्म करके, इस सरकार और चुनाव आयोग ने हर भारतीय की आवाज पर हमला किया है। इस सरकार ने चोरी किए गए वोटों के दम पर जो कुछ भी किया है, वह गैर-कानूनी है। वोट चोरी से चुना गया सांसद गैर-कानूनी तरीके से अपनी सीट पर

बैठा है, और उस सांसद के समर्थन से पास हुआ हर कानून गैर-कानूनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पार्टी ने तीन साल से वोट चोरी को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उजागर करने का काम किया है अब चुनाव आयुक्त गण खुद इसे स्वीकार कर सच्चाई उजागर कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ने देशद्रोह किया है। वो अभी

इस्तीफा दें और गवाह बन जाएं। वयूँकी कॉंग्रेस पार्टी ने वोट चोरी के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन का बिगुल फुंक दिया है वोट चोरी की साजिश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूरी जांच होगी। जिला अध्यक्ष जय प्रकाश भाई पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि निर्वाचन आयोग का निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता संस्थागत जवाबदेही, एसआईआर प्रक्रिया और मतदाता सूची की विश्वसनीयता, निर्वाचन आयोग आईटी प्रणाली और डेटा प्रबंधन, मतदाता सूची में किए गए बदलाव की स्वतंत्र समीक्षा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त संबंध मे उठे आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस इसकी मांग करती है । यदि ये मांगें पूरी नहीं की गईं तो

कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। कार्यक्रम में पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्यासी मुन्ना सिंह बरही विधानसभा के पूर्व प्रत्यासी अरूण साहू प्रदेश कांङीनेटर बिनोद कुशवाहा ने भी संबोधित किया। जिला कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष निसार ने बताया कि कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन नगर अध्यक्ष परवेज अहमद ने किया। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के पदाधिकारीगण पूर्व जिला अध्यक्षगण जिला के पदाधिकारीगण वरिष्ठ कांग्रेसजन युवा कांग्रेस, एनएसयुआई, महिला कांग्रेस, कांग्रेस सेवादल प्रखंड, मंडल, पंचायत तथा सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण के अतिरिक्त हजारों की संख्या मे कांग्रेसी कार्यकर्तागण उपस्थित थे ।



बिभा संवाददाता

हजारीबाग: इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर उठे विवाद के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) हजारीबाग जिला समिति ने रविवार को जिला परिषद चौक पर उनका पुतला दहन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजीव कुमार बेदिया ने की। इससे पूर्व बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता हीराबाग चौक स्थित जिला कार्यालय में एकत्रित हुए, जहां से नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में जिला परिषद चौक पहुंचे। वहां कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया तथा उनके इस्तीफे की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष संजीव कुमार बेदिया

ने कहा कि हाल में सामने आई खबरों ने देश की जनता के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर जनता का विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और यदि किसी अधिकारी की कार्यशैली या भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए जवाबदेही तय होना आवश्यक है।जिला सचिव नीलकंठ महतो ने कहा कि देश का लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रणाली पर आधारित है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन तथ्यों का खुलासा मीडिया रिपोर्टों में हुआ है, उससे आम नागरिकों के बीच शंकाएं पैदा हुई हैं। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराई जानी चाहिए और यदि आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई होनी चाहिए।

संक्षिप्त खबरें

लातेहार में आज चला वाहन जांच अभियान 50,500 रुपए का चालान कटा

लातेहार (बिभा): सड़क पर बढ़ती दुर्घटना को लेकर उपायुक्त संदीप कुमार के निर्देशानुसार ज़िला परिवहन पदाधिकारी उमेश मंडल, पुलिस उपाधीक्षक प्रदीप कुमार और प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक राम लखन बर्नवाल के द्वारा सोमवार को लातेहार थाना के सफ़िक्ट हाउस, लातेहार के पास बढ़ती सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु दुपहिया- तीनपहिया वाहनों की जाँच की गयी जाँच में दोषी वाहनों के विरुद्ध कुल 48 वाहनों से 50,500/ रू राशि का ई-चालान किया गया तथा सड़क सुरक्षा के बारे में वाहन चालकों को जागरूक भी किया गया । आए दिन लातेहार जिले में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिससे कई लोगों की जान चली गई, परिवहन विभाग के पदाधिकारी ने कहा और लोगों से अपील की दो चकिया और तीन चकिया एवं चार चकिया वाहन चालकों रोड पर धीमी गति से और देख समझकर गाड़ी चलाएं क्योंकि एक समझदारी से लोगों की जान बच सकती है, इसी तरह वाहन जांच अभियान आगे भी चलता रहेगा।

चेतना शाखा काछटा मासिक स्वास्थ्य जांच शिविर संपन्न

रामगढ़(बिभा): मारवाड़ी युवा मंच, रामगढ़ कैंट चेतना शाखा द्वारा दिनांक 28 सितंबर को प्रातः 6:45 बजे, हनुमान मंदिर, संकट मोचन मंदिर, थाना चौक में छठे मासिक स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में लगभग 29 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर में शूगर, कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, यूरिक एसिड, टीएसएच, टी3, एचबीए1सी, लिपिड प्रोफाइल, विटामिन बी12, विटामिन डी, थायरॉयड एवं फुल बॉडी चेकअप सहित विभिन्न आवश्यक स्वास्थ्य जांच की गई। इस सेवा कार्य में चेतना शाखा के लगभग 6 सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाते हुए शिविर को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। शाखा द्वारा नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे स्वास्थ्य जांच शिविर समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने तथा समय पर स्वास्थ्य संबंधी जांच एवं सावधानी के महत्व का संदेश देने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है।

जीतो रांची में पहली बार एजीएम के बाद चुनाव, पायल सेटी बनीं चेयरमैन



हजारीबाग/रांची(बिभा): जीतो रांची के कार्यकाल 2026-28 के लिए रविवार को एजीएम के पश्चात चुनाव प्रक्रिया आयोजित की गई। जीतो रांची के इतिहास में यह पहली बार है, जब एजीएम के बाद चुनाव के माध्यम से नई नेतृत्व टीम के गठन को प्रक्रिया पूरी की गई। चुनाव में कुल 72 मतदाताओं ने हिस्सा लिया। संगठन में तीन निदेशक पदों के लिए चुनाव होना था, जिसके लिए एच नरनांकन प्राप्त हुए। चुनाव मैदान में पायल सेटी, विशाल जैन, कुणाल जैन और प्रतीक जैन शामिल थे।मतदान में पायल सेटी को 71, विशाल जैन को 68 और कुणाल जैन को 42 मत प्राप्त हुए। प्राप्त परिणामों के आधार पर तीन निर्वाचित निदेशकों द्वारा कार्यकाल 2026-28 के लिए नई हेड टेबल का गठन किया गया।नई हेड टेबल में चेयरमैन के रूप में पायल सेटी, चीफ सेक्रेटरी के रूप में कुणाल जैन तथा टेज़रर के रूप में सीए मोहित जैन को जिम्मेदारी सौंपी गई।चुनाव प्रक्रिया के सुचारु संचालन के लिए प्रदीप जी जैन को आरओ नियुक्त किया गया था। उन्होंने निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार चुनाव संपन्न कराया। नई हेड टेबल का विधिवत कार्यभार आगामी निर्धारित कार्यक्रम में किया जाएगा। इस अवसर पर वर्तमान पदाधिकारी नई टीम को संगठन का कार्यभार सौंपेगे।

बालूमाथ मुख्य पथ से हटेगा अतिक्रमण, कोयला वाहनों के प्रदूषण पर लगेगी रोक: उपायुक्त

लातेहार। बालूमाथ मुख्य पथ पर बढ़ते अतिक्रमण और कोयला वाहनों के परिचालन से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इन गंभीर समस्याओं के समाधान को लेकर उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी संदीप कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। डीसी ने मुख्य पथ को अविलंब अतिक्रमण मुक्त कराने और कोयला ढुलई से फैल रहे प्रदूषण पर प्रभावी रोकथाम के कड़े निर्देश दिए हैं। मामले के स्थायी समाधान के लिए 3 अक्टूबर को बालूमाथ प्रखंड कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है।

बालूमाथ मुख्य पथ पर कई स्थानों पर दुकानदारों और स्थानीय लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिए जाने



के कारण आए दिन जाम की स्थिति बन रही है, जिससे ग्रामीणों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि नियमानुसार अभियान चलाकर सभी अतिक्रमित स्थलों को शीघ्र खाली कराया जाए और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

उपायुक्त ने कहा कि आम लोगों के आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अतिक्रमण हटाने और कोयला वाहनों के परिचालन से जुड़ी समस्याओं का हल सभी संबंधित पक्षों के साथ समन्वय बनाकर निकाला जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यवसायियों और

एसआईआर के विरोध में झामुमो का प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

लातेहार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने सोमवार को लातेहार जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय गेट के समक्ष प्रदर्शन करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन किया।

प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची में पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने एसआईआर और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक पात्र मतदाता के मताधिकार की रक्षा जरूरी है। किसी भी पात्र मतदाता का नाम



मतदाता सूची से नहीं हटना चाहिए। बैद्यनाथ राम ने आरोप लगाया कि एसआईआर के माध्यम से गैर-भाजपा समर्थक मतदाताओं के नाम प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि झामुमो लोकतांत्रिक तरीके से इस मुद्दे पर अपना विरोध जारी रखेगा। झामुमो जिलाध्यक्ष लाल मोती नाथ शाहदेव ने कहा कि पार्टी लगातार एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाती रही है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से जुड़े किसी भी निर्णय में पारदर्शिता जरूरी है तथा किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं हटना चाहिए। उन्होंने बताया कि पार्टी मुख्य चुनाव

आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के समक्ष भी अपनी मांग रखने की बात कह चुकी है।प्रदर्शन के दौरान झामुमो नेताओं ने एसआईआर को लेकर कई आरोप लगाए और दावा किया कि इससे बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रभावित हो सकते हैं। हालाँकि, इन आंकड़ों और राजनीतिक आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं की गई है। कार्यक्रम में बीस सूत्री उपाध्यक्ष अरुण दुबे, अशोक पाण्डेय, सौरभ श्रीवास्तव, रिकू कच्छप, बुद्धेश्वर उरांव, प्रभात कुमार, अंकित पाण्डेय, शीला देवी, आर्सेन तिक्रिा, सुशील कुमार यादव समेत बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे।

परियोजना स्तरीय व्यंजन प्रतियोगिता और पोषण प्रदर्शनी का आयोजन, पौष्टिक आहार के प्रति किया गया जागरूक

लातेहार। राष्ट्रीय पोषण माह 2026 के तहत लातेहार में पोषण और संतुलित आहार को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में लातेहार सदर प्रखंड परिसर स्थित सभागार में परियोजना स्तरीय व्यंजन प्रतियोगिता और पोषण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने स्थानीय एवं पौष्टिक खाद्य सामग्री से तैयार विभिन्न व्यंजनों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं और आम लोगों को पोषण के महत्व के प्रति जागरूक करना रहा। प्रदर्शनी के



माध्यम से यह बताया गया कि रोजमर्रा के भोजन में अलग-अलग खाद्य समूहों को शामिल कर पोषण स्तर को बेहतर किया जा सकता है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाले टेक-होम राशन (ळरूफ) से अलग-अलग पौष्टिक व्यंजन तैयार करने की जानकारी भी दी गई।मोटे अनाज और

स्थानीय खाद्य पदार्थों पर जोर कार्यक्रम में मोटे अनाज सहित स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया। स्वस्थ और विविध भोजन के व्यावहारिक तरीकों को प्रदर्शनी और व्यंजन प्रतियोगिता के माध्यम से

समझाया गया।राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का मुख्य विषय ह्रहमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारीह्र है। इस वर्ष अभियान में आहार विविधता, पर्याप्त प्रोटीन, ताजा पौष्टिक भोजन और आंगनबाड़ी केंद्रों में सामुदायिक भागीदारी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र से परियोजना और फिर जिला स्तर तक प्रतियोगिता।जिला बाल कल्याण पदाधिकारी सविता कुमारी ने पत्रकारों को बताया कि पोषण माह के तहत पहले 25 सितंबर को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके बाद सेक्टर स्तर पर कार्यक्रम हुआ

और अब परियोजना स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को जिला स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। परियोजना स्तर से चयनित उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सहायिकाओं को जिला स्तर पर सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा। सविता कुमारी ने बताया कि पोषण माह का उद्देश्य केवल भोजन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों को यह समझाना भी है कि उपलब्ध और स्थानीय खाद्य सामग्री का बेहतर उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके माध्यम से महिलाओं और परिवारों को संतुलित

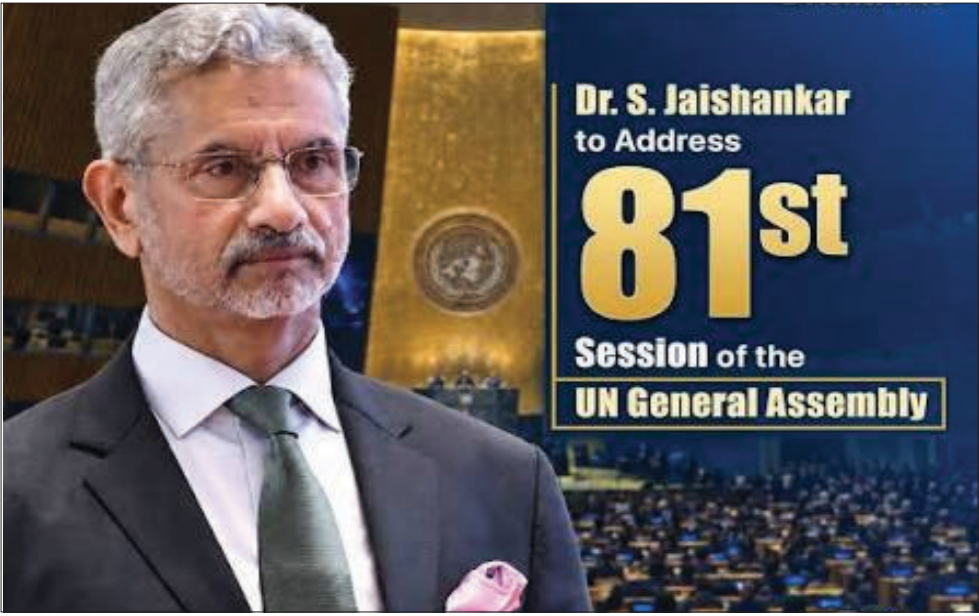
एवं पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह 9 सितंबर से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषण, स्वास्थ्य और शुरूआती बाल विकास से जुड़ी सामुदायिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया गया है। कार्यक्रम में पोषण संबंधी जानकारी, व्यंजन प्रदर्शन और स्थानीय खाद्य पदार्थों के उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। आयोजकों ने कहा कि बेहतर पोषण के लिए परिवार और समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

पाकिस्तान के बेतुके सवाल: भारत के सटीक जबाब



ललित गर्ग

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 26 सितंबर को महासभा में सटीक, तीक्ष्ण एवं प्रभावी वक्तव्य में पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि एक 'सीरियल प्रैक्टिशनर ऑफ टेररिज्म' ने एक दिन पहले तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया और आतंकवाद को सामान्य बनाने तथा उसके परिणामों से बचने का प्रयास किया, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।



पर भी आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगाता है और अपने यहां होने वाली हिंसक घटनाओं के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता है। इन परस्पर आरोपों की सच्चाई और प्रमाण अलग-अलग मामलों में जांच का विषय हो सकते हैं, लेकिन इतना निर्विवाद है कि पाक आतंकवाद को पोषित कर भारत की शांति का भंग करता रहा है, इन आतंकी घटनाओं ने दोनों देशों की जनता को भारी मानवीय, आर्थिक और सामाजिक किमत्त चुनता पर मजबूर किया है। तो फिर सवाल उठता है-पाकिस्तान आखिर कब यह स्वीकार करेगा कि आतंकवाद किसी भी राष्ट्र की स्थायी विदेशी नीति नहीं बन सकता? आतंकवाद यदि किसी देश के लिए रणनीतिक सफल बनता है तो अंततः वही साधा-उस देश की आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता के लिए भी समस्या बन सकता है। पाकिस्तान स्वयं लंबे समय से आतंकवादी हिंसा से जूझ रहा है। ऐसे में उसके सामने यह ऐतिहासिक अवसर है कि वह आतंकवाद के प्रश्न को केवल भारत-विरोधी दृष्टिकोण से न देखकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य के संदर्भ में भी देखे। आतंकवाद के रूढ़िवादी केवल किसी दूसरे देश की मांग पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। दूसरा प्रश्न कश्मीर का है। पाकिस्तान ने इस बार भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाया। लेकिन लगभग आठ दशक से चली आ रही इस बहस ने लोक सभित का

दिखा है कि केवल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बयान देने से समस्या का समाधान नहीं होता। कश्मीर के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच अविश्वस्य बढ़ता है, सुरक्षा तनाव पैदा होता है और दोनों देशों की विकास प्रार्थनाएँ अप्रभावित होती हैं। यदि पाकिस्तान वास्तव में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता चाहता है, तो उसे यह विचार करना होगा कि कश्मीर को अपनी विदेश नीति के लिये क्या केंद्र में रखकर वह अपने नागरिकों के भविष्य के स्थायी हवा हासिल कर रहा है। हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का उल्लेख करना और घेरलू समस्याओं को पीछे छोड़ देना किसी भी देश के लिए दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता। तीसरा और शायद सबसे गंभीर प्रश्न पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और वहन के आम नागरिक की ज़िंदगी का है। महंगाई, रोजगार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे किसी भी सरकार के लिए मूलभूत जिम्मेदारियाँ हैं। विदेश नीति तभी सार्थक होती है जब उसका अंतिम उद्देश्य देश के नागरिकों के जीवन को सुस्थिर, समृद्ध और सम्मानजनक बनाना हो। पाकिस्तान के लिए यह समय इस बात पर गंभीरता से विचार करने का है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ राजनीतिक और कूटनीतिक अभियान चलाने की तुलना में उसकी जनता की आर्थिक आवश्यकताओं, संरक्षण में स्थिरता और मानव विकास पर अधिक ऊर्जा लगाना कितना आवश्यक है।

यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि भारत-पाक संबंधों को

केवल आरोप-प्रत्यारोप के चरमों से न देखा जाए। भारत की अपनी सुरक्षा चिंताएं वास्तविक हैं और किसी भी सरकार को पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है। जयशंकर ने भी संयुक्त राष्ट्र में भारत के आत्मरक्षा के अधिकार और आतंकवाद के विरुद्ध शून्य-सहिष्णुता की बात कही। लेकिन इसी के साथ क्षेत्रीय शांति के लिए यह भी आवश्यक है कि आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ता और संवाद की संभावनाओं के बीच संतुलन खोजा जाए। संवाद तभी सार्थक हो सकता है जब हिंसा और आतंकवाद के प्रश्न पर स्पष्टता हो। पाकिस्तान को यह भी समझना होगा कि दुनिया आज केवल बयान नहीं सुनती, बल्कि नीतियों और व्यवहार को भी देखती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मूल उद्देश्य ही बहुपक्षीय संवाद, शांति और सहयोग के लिए मंच उपलब्ध कराना है। यदि इस मंच का इस्तेमाल एक-दूसरे के विरुद्ध आरोपों को दोहराने में ही होता रहे, तो दोनों देशों के नागरिकों को उससे क्या हासिल होगा? भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संयंत्र पड़ोसी हैं। इसलिए इनके बीच तनाव केवल द्विपक्षीय समस्या नहीं रहता, उसका प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता पर पड़ सकता है।

आज पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा आत्मयंत्रण यही होना चाहिए कि वह अपने भविष्य को किस आधार पर निर्मित करना चाहता है-पुराने विवादों, कश्मीर-केन्द्रित राजनीति और आतंकवाद के आरोपों के आधार पर या आर्थिक विकास, शिक्षा, रोजगार, संस्थागत मानववृत्ति और क्षेत्रीय सहयोग के आधार पर ? भारत के सामने भी चुनौती यही है कि सुरक्षा से सम्पन्नता किए बिना दक्षिण एशिया में स्थायी शांति की संभावनाओं को खुला रखा जाए। पाकिस्तान कब बतलेगा, इसका उत्तर कोई दूसरा देश नहीं दे सकता। परिवर्तन अतः पाकिस्तान को अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत निर्णयों और नीति-निर्माताओं पर निर्भर करेगा। लेकिन दिशा स्पष्ट है आतंकवाद को किसी भी रूप में राजनीतिक साधन न बनने देना, अपनी जनता को आर्थिक जरूरतों को प्राथमिकता देना, कश्मीर के नाम पर लगातार टकराव को नीति से आगे बढ़ना और पड़ोसियों के साथ संबंधों को हिंसा के बजाय विश्वास तथा पारस्परिक समान के आधार पर विकसित करना। यदि पाकिस्तान यह रास्ता चुनता है तो उसका लाभ केवल भारत को नहीं, स्वयं पाकिस्तान के नागरिकों और पूरे दक्षिण एशिया को मिलेगा। और यदि वह पुराने रास्ते पर ही चलता रहा, तो सबसे बड़ा प्रश्न दुनिया से अधिक उसके अपने नागरिकों के सामने खड़ा होगा-आखिर कब तक अतंती की राजनीति भविष्य की पीढ़ियों का वर्तमान तय करती रहेगी ?

संपादकीय

हरियाणवी प्रतिभाओं को संबल

हरियाणा सरकार के उस फैसले का स्वागत ही किया जाना चाहिए, जिसमें सरकार ने राज्य में नई खोजों को प्रोत्साहन देने के लिये पचास हजार रुपये तक की, पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय किया है। निश्चय ही इस कदम से उन छात्रों को संबल मिलेगा जो सीमित संसाधनों में राज्य व देश के लिये कुछ महत्वपूर्ण खोज करने का संकल्प रखते हैं। लेकिन पेटेंट तो महज एक शुरुआत भर है। असली मुश्किल सवाल यह है कि पेटेंट सर्टिफिकेट मिलने पर मेधावी युवा क्या करेंगे। निर्विवाद रूप से भारत में प्रतिभावान छात्रों, रिसर्च पेपर्स या पेटेंट की कोई कमी नहीं है। दरअसल, कमी है तो उस इकोसिस्टम की जो किसी विचार या आईडिया को लैब या विश्वविद्यालय प्रोजेक्ट से निकालकर व्यावसायिक दृष्टि से सफल उत्पाद बनाता है। यही वजह है कि छात्रों को पेटेंट के लिये पैसे देने में मदद करने वाली नीति के साथ-साथ प्रोटोटाइपिंग, टैस्टिंग, बौद्धिक संपदा संरक्षण और नये विचार को मार्केट तक पहुँचाने में मदद मिलनी चाहिए। अन्यथा खोज व अनुसंधान अर्थव्यवस्था के महज पेटेंट कल्चर तक ही सिमट जाने का खतरा पैदा हो सकता है। जिसमें समाधान खोजने के बजाय पेटेंट फाइल करने पर इनमर जाता है। सही मायने में इसके लिये कारणर समाधान तलाशने हेतु विश्वविद्यालयों को उद्योग जगत से और करीब से जोड़ने की जरूरत है। छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं की पहचान करने, कंपनियों और सरकारी संस्थानों के साथ काम करने और ऐसे उत्पाद बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिनके लिये रजिस्ट्रेशन उपयोगकर्ता की पहले से पहचान हो सके। सही मायने में चिन्तन में शोध-अनुसंधान का वातावरण बनाने के लिये सामाजिक व्यावहारिक पक्षों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। नई खोज करने वाले प्रतिभागियों को वित्तीय मदद, उत्पादन के लिये उपयोगी ढांचा, रेगुलेशन और मार्केटिंग से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद की जानी चाहिए। हरियाणा के लिये यह अवसर बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य के विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान खेती से जुड़ी विभिन्न तकनीकों, जल प्रबंधन, उत्पादन, हेल्थकेयर और स्वच्छ ऊर्जा आदि अन्य क्षेत्रों में इनवैशेन के इंसान बन सकते हैं। इसके लिये सिर्फ एक बार प्रोत्साहन राशि देने के बजाय लगातार निवेश करने की जरूरत होगी। राज्य को अपनी पेटेंट पॉलिसी की सफलता को सिर्फ पेटेंट की फीस की प्रतिपूर्ति वाले आवेदनों की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से अपनी सफलता का मूल्यांकन करना चाहिए कि उन पेटेंटों से व्यवहार में क्या हासिल हुआ। मसलन राज्य में कितने स्टार्ट-अप बने। राज्य में कितनी टेक्नोलॉजी का व्यवसायीकरण हुआ। उससे राज्य में नौकरियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। इस बात में दो राय नहीं हो सकती है कि पेटेंट किसी विचार या खोज को सुरक्षा देता है। लेकिन वह इस बात की गारंटी कदापि नहीं है कि व्यवहार में उसका उपयोग राज्य व देश के लिये कितना लाभदायक होगा। यही वजह है कि हरियाणा को व्यवहार में ज्यादा से ज्यादा समस्याओं के समाधान करने वाले उद्यमों और उत्पाद बनाने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।

चिंतन-मनन

गुरु की स्वीकार्यता

हर वक्त संसार को गुरु की दृष्टि से देखो। तब यह संसार मिलन नहीं बल्कि प्रेम, आनन्द, सहयोगिता, दया आदि गुणों से परिपूर्ण, अधिक उत्सवपूर्ण लगता। तुम्हें किसी के साथ संबंध बनाने में भय नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पास आश्रय है। पर के अन्दर से तुम बाहर के वज्रपात, आंधी, वर्षा व कटती धूप देखोगे। भीतर वातानुकूलित व्यवस्था है- शीतल और शान्त। बाहर गर्मी और अशांति है पर तुम परेशान नहीं होते, क्योंकि कुछ भी तुम्हें बेचैन और विचलित नहीं कर सकता। कोई तुम्हारी पूर्णता नहीं छीन सकता। वहीं गुरु को उद्देश्य। संसार के सभी संबंध उलट-पुलट हो जाते हैं। संबंध बनते हैं और टूटते हैं। यहां राग भी है, द्वेष भी। यही संसार है। पर गुरु। कोई संबंध नहीं, गुरु को मौजूदगी होती है। गुरु का सान्निध्य अनुभव करो। गुरु को अपने संसार का अंश मत बनाओ। संसार का हिस्सा बनते ही, वही अग्रिय भावनाएं उठती हैं- उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वह उनका अधिक प्रिय है, मैं नहीं हूं। जीवन में गुरु का सान्निध्य सभी संबंधों में पूर्णता लाता है। यदि गुरु के निकट अनुभव नहीं कर रहे, तो यह तुम्हारे मन, धारणा, अहंकार के कारण है। जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, अंतरंग है, उसे गुरु के साथ बांटो। जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, आंतरिक है, जब तक तुम उसे गुरु को नहीं व्यक्त करते, तब तक निकटता का अनुभव नहीं कर सकते।

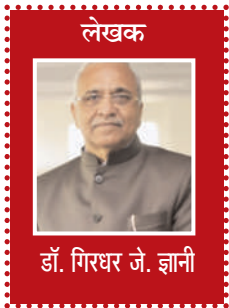


ऋतुपर्ण दवे

आज पंचम हृदय दिवस है। पिछले एक दशक में, स्वास्थ्य हृदय के मालिकों को समझने वालों की संख्या में वृद्धि जबरन हुई है लेकिन संख्या ही दुखद पहलू यह भी है कि हृदय संबंधी विकारों से पीड़ित लोगों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दरअसल, गतिहीन जीवनशैली, खराब खान-पान और बढ़ता तनाव लोगों को आज दिनचर्या की प्रभावित कर रहा है। इसी के चलते हृदय रोग दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है। लेकिन यह भी सही है कि जागरूकता, नियमित जांच और स्वस्थ जीवनशैली के जरिए हृदय संबंधी बहुतेरी समस्याओं को रोका जा सकता है। या बेहतर जीवनशैली से प्रबंधित किया जा सकता है।

स्वास्थ्य संबंधी इन्हीं सब कारणों से विश्व हृदय की परिकल्पना को साकार कर गया तब विशेषकर विश्व में मानने के निश्चय किया गया दिन लक्ष इस रोग की बारीकी और शुरुआती लक्षण पहचानने में मदद मिल सके। कम से कम जागरूकता तो आए कि लोग जरूरत पड़ने पर प्राथमिक उपचार और त्वरित स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने की दिशा में जागरूक हो सकें। विश्व स्वास्थ्य के अनुसार, विश्व में सबसे ज्यादा मौतें हृदय होती हैं। हर साल लगभग एक करोड़ अस्सल लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। विश्व हृदय दिवस को शुरुआत वर्ष 2000 में हृदय महासंघ द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ की गई। इसका उद्देश्य हृदय रोगों और रोकथाम के लिए आवश्यक उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। यह दिन हर साल सितंबर को मनाया जाता है, जो दुनिया भर के स्वास्थ्य संगठनों और समुदायों को हृदय स्वास्थ्य केन्द्रित करने और निवारक उपायों को प्रोत्साहित के लिए एक साथ लाता है।

हृदय रोग के बढ़ते जोखिम और इसके सामझने, चेतनाई सकेतों को पहचानने और आदतों को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डालने लिए इस पहल की शुरुआत की गई थी जो प्रतीत हो रही है। अब यह विगत 26 वर्षों से



डॉ. गिरधर जे. ज्ञानी

भातर के कई हिस्सों में आज भी एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक मरीज की जानकारी पहुंचाने का मुख्य जरिया खुद मरीज ही है। वह हर बार अपना पुराना मेडिकल रिपोर्ट लेकर जाती है- कर्मजों की फाइल, मोबाइल में जांच की सर्वरों या फिर सिर्फ अपनी याददश्त के भरोसे। इलाज के हर चरण में कई जानकारी का होना होता है, लेकिन अक्सर वह अगले डॉक्टर या अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती। अस्पतालों के अपिल इस कमी को दूर करना लंबे समय तक प्रार्थमिकता नहीं रहा। जब स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने की बात हुई, तो मुख्य सवाल यही रहा कि इसमें कितना खर्च आएगा और अस्पतालों को अपनी व्यवस्था में कितना बदलाव करना पड़ेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई नई डिजिटल व्यवस्था एक सप्ताहों में लागू नहीं की जा सकती। अस्पतालों में वर्षों पुराने सॉफ्टवेयर, अलग-अलग तरह की कामना करने की प्रक्रियाएं और डिजिटल-अलग तकनीक के इस्तेमाल का अलग-अलग स्तर है। छोटे अस्पतालों के लिए तकनीक पर खर्च किया गया हर रुपया बिस्तरे, उपकरणों और कर्मचारियों पर होने वाले

खर्च से जुड़ होता है। इसलिए हमेशा यह सवाल रहा कि क्या 'है' व्यवस्था वास्तव में ऐसी समस्या का समाधान करेगी, जिसका समाधान जरूरी है। अब सवाल बदल गया है। ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मरीजों की जानकारी अलग-अलग जगह बंटी रहने की वजह से अस्पतालों और मरीजों को पहले से कितना नुकसान हो रहा है। मरीज के इलाज का पूरा सफर इस समस्या को साफ दिखाता है। वह पहले किसी स्थानीय डॉक्टर को दिखा सकती है, फिर किसी जांच केंद्र पर जांच कर सकती है, उसके बाद विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह ले सकती है और अंत में अस्पताल में भर्ती हो सकती है। इलाज के हर चरण में मरीज से जुड़ी 'है' जानकारी तैयार होती है, लेकिन वह जानकारी अक्सर डॉक्टर, विलिनिक और जांच केंद्र के बीच आगे नहीं पहुंचती। इसके बाद क्या होता है, वह हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री उपलब्ध नहीं होती, पूरी जांच दोबारा करनी पड़ती है, इलाज में अनावश्यक देरी होती है और ऐसी जानकारी जुटने में घंटों लग जाते हैं जो पहले से कहीं और मौजूद होती है। लंबे समय तक डेटा को अस्पताल या संस्था की अपनी संपत्ति की तरह देखा गया, जिसे आपन पास रखा जाए। जबकि अस्पताल में यह ऐसी जानकारी है, जिसके मरीज के साथ और बढ़ना चाहिए। अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग प्राक्ख और एक-दूसरे से मेल न खाने वाली डिजिटल व्यवस्थाओं ने इस समस्या को और बढ़ाया है। अब जानकारी

को अलग-अलग जगह बंद रखने की कीमत इतनी बढ़ गई है कि इसका मुकाम मरीजों और अस्पतालों, दोनों को हो रहा है। इसी वजह से निजी अस्पतालों ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी एबीडीएम को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि अलग-अलग डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक समान मानकों की जरूरत है। इससे यह पुनिश्चित किया जा सकता है कि मरीज जहां भी इलाज कराए, उसकी जरूरी स्वास्थ्य जानकारी अगले डॉक्टर या अस्पताल के काम आ सके।

दुनिया के अलग-अलग देशों के अनुभव बताते हैं कि जब मरीज की स्वास्थ्य जानकारी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं पहुंचती, तो मरीज को खराब अनुभव हो सकता है, एक ही जांच बार-बार हो सकती है और इलाज में देरी हो सकती है। इसके विपरीत, अलग-अलग स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच बेहतर तालमेल से जांचों की दोहराव वाली जरूरत और अस्पताल में देवागर्ष भती होने के मामलों में कमी देखी गई है।

प्रशासन के स्तर पर भी यही समस्या दिखाई देती है। एक अस्पताल बंद की वार्ड कमिनिये और भुगतान करने वाली संस्थाओं के साथ काम करता है। इनमें से हर संस्था की अपनी डिजिटल व्यवस्था और अपने तरीके होते हैं। जब ये व्यवस्थाएं एक-दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाती, तो बीमारियों की प्रक्रिया देवागर्ष धीमी और महंगी

हो जाती है। इसका सीधा असर अस्पताल की वित्तीय टीम और उसके पैसے के प्रवाह पर पड़ता है।

नेशनल हेल्थ क्लेमस एक्सचेंज (एनएचसीएक्स) इसी समस्या को दूर करने की कोशिश करता है। यह बीमा कंपन की प्रक्रिया को एक समान बनाने पर काम करता है। चाहे डॉक्टर के लिए जरूरी जांच रिपोर्ट हो या अस्पताल और बीमा कंपनी के बीच भेजा जाने वाला दावा, अगर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं पहुंच सकती, तो यह पूरी व्यवस्था की कमी है। एनएचसीएक्स और अनुष्ठान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों पर काम करते हैं, लेकिन दोनों के पीछे मूल सोच एक ही है— जानकारी सुविधित तरीके से, एक समान व्यवस्था के तहत और जरूरी सुविधाओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके।

लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल व्यवस्था सिर्फ ऊपर से लागू नहीं की जा सकती। इसे डॉक्टरों, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाएं देने वालों के साथ मिलकर तैयार करना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी दी है कि अगर डिजिटल व्यवस्था अलग-अलग और केवल ऊपर से तय करके लागू की जाती है, तो इससे स्वास्थ्य व्यवस्था में बिखराव और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर प्रशासनिक बोझ बढ़ सकता है। इसलिए अलग-अलग प्रणालियों को आपस में जोड़ना ही मुख्य लक्ष्य होना चाहिए।

भारत में यह बात खास तौर पर महत्वपूर्ण

है, क्योंकि यहां निजी स्वास्थ्य क्षेत्र बहुत विविध है। महानगर का एक बड़ा कॉर्पोरेट अस्पताल और दूसरे या तीसरे शहर का छोटा अस्पताल एक-जैसी तकनीक, संसाधन या डिजिटल स्वास्थ्य लागू करने की क्षमता नहीं रखते। छोटे अस्पतालों में अलग से तकनीकी यातनाएं नहीं हो सकती। अगर डिजिटल स्वास्थ्य सही तरीके से नहीं बनाई गई, तो उसे लागू करने का अतिरिक्त बोझ भी अस्पताल पर पड़ सकता है। इसलिए डिजिटल स्वास्थ्य को अपनाने की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अस्पतालों को कितना व्यावहारिक सहयोग मिलता है और नई स्वास्थ्य कतिनी के इलाज के मौजूदा तरीके के साथ निरन्ती आसानी से जुड़ पाते हैं। आगुमान भारत डिजिटल मिशन के दूर और एमएचसीपीएस के समर्थक के रूप में, एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (एचपीआई) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रतिकरण के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा देने वालों को इन डिजिटल स्वास्थ्यओं का व्यावहारिक लाभ समझाना, अलग-अलग तरह के अस्पतालों में इनके इस्तेमाल को बढ़ावा देना और अस्पतालों के अनुभवों को उन लोगों तक पहुंचाना है, जो इन डिजिटल स्वास्थ्यओं को तैयार कर रहे हैं। निजी स्वास्थ्य क्षेत्र सिर्फ भारत का डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था का इस्तेमाल करने वाला नहीं रह सकता। अस्पताल इस व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण

उपयोगकर्ताओं में हैं, इसलिए उन्हें इसी बाना में भी सत्रिय भूमिका निभानी होगी। अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा देने वालों को जानकारी के अलग-अलग जगह बढ़ें हों और आपसी तालमेल की कमी का ज अनुभव होता है, उसे देखा में डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था को आगे बढ़ने क योजना में शामिल करना होगा।

आगे का काम कर हासों में बांज सकता है। महला, अस्पतालों को ऐसी डेटा अलग-अलग को खस करना होगा, जिसक अलग-अलग बंद पड़े रहना किसी के काम नहीं आता।

दूसरा, स्वास्थ्य तकनीक से जुड़े कर्मियों को ऐसे उपाय और सफायेर बाने होंगे जो एक-दूसरे के साथ आसानी से काम कर सकें तीसरा, चिकित्सा संस्थाओं और संगठनों को छोट अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों को डिजिटल व्यवस्था अपनाने के शुरुआती चरण में मदद करनी होगी। चौथा, नीति बाने वालों को ऐसे समान और व्यावहारिक मानक तन करने होंगे, जिन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी लोग अपना सके अनुमान भारत डिजिटल मिशन क सफलता तन मानी जाएगी, जत अस्पतालों, डॉक्टरों और मरीजों के स्वास्थ्य व्यवस्था में विखुरव काम होता हुआ महसूस होगा। जब ऐसा होगा और ऐसा होगा मरीज है तब डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था को सभी को इलाज कर अधिक बेहतर और प्रभावी तरीका माना जाएगा।

(लेखक एसोसिएशन ऑफ हेल्थटेक्न प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (एएचपीआई) के महानिर्देशक हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत हैं।)



काम को आसान बना देंगे ये स्मार्ट ट्रिक्स

- बना सकते हैं। ये शानदार किचन ट्रिक्स आपका काम आसान करने के साथ-साथ खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा।
- बादाम या टमाटर छिलने के लिए पहले उन्हें 5-10 मिनट तक पानी में उबालें। इससे इनके छिलके आसानी से निकल जाएंगे।
 - प्याज को काटने और लहसुन को छिलने से पहले उसे 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। इससे प्याज काटते समय आंखें नहीं आएंगे और लहसुन के छिलके भी आराम से उतर जाएंगे।
 - सूखे मेवे या ड्राईफ्रूट्स को काटने से पहले 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इससे यह सॉफ्ट हो जाएंगे और आप इन्हें आसानी से काट सकेंगी।
 - मशरूम को कभी भी पानी से न धाएं। क्योंकि यह पानी को सोख लेते हैं और कपाते समय पानी छोड़ देते हैं, जिससे सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है। इसकी बजाए आप मशरूम को गीले कपड़े से साफ करें।
 - अगर आप पनीर बना रही हैं तो उसमें थोड़ा-सा ऑयल लगा दें। इससे यह बर्तन के साथ चिपकेगे नहीं।
 - शहद की शुद्धता पता लगाने के लिए उसकी कुछ बूंदें कांच की बोतल या गिलास में डालें। अगर शहद तले पर बैठ जाए तो शुद्ध है और अगर वो पानी में मिक्स हो जाए तो मिलावटी है।
 - अगर आप बिरयानी या कोई ग्रेवी वाली डिश बना रही है तो उसमें दही डालने से पहले अच्छी तरह फेंट लें। इससे खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। इसके अलावा सब्जियां उबालने के बाद इसके पानी को दाल बनाने में इस्तेमाल करें। इससे दाल का स्वाद बेगुना हो जाएगा।
 - चावल पकाने से पहले उससे अच्छी तरह से धो लें। इससे चावल में मौजूद स्टार्च निकाल जाएगा और चावल पकने के बाद चिपचिपा नहीं होगा। इसके अलावा चावल की खीर बनाते समय बर्तन में पहले थोड़ा-सा पानी डाल दें। इससे दूध बर्तन के तले पर नहीं चिपकेगा।
 - फलों को काटने के बाद उसके ऊपर अच्छी तरह से नींबू छिड़ककर फ्रिज में स्टोर करें। इससे फल पूरा दिन ताजे रहेंगे और इनका रंग भी खराब नहीं होगा।



पर्सनल स्पेस में प्रोफेशनल लाइफ हो रही है हावी तो इन टिप्स को करें फॉलो

- शेड्यूल बनाएं**
- अगर आप वर्क-फॉर्म-होम और हाइब्रिड वर्किंग के तौर पर काम कर रहे हैं तो आपको समय पर लॉग इन करना चाहिए और समय पर ही लॉग आउट करना चाहिए। अगर आपका बॉस आपको रोजाना ओवरटाइम काम करने को कह रहा है तो आपको उसकी शिकायत करनी चाहिए।
- ब्रेक लें**
- वर्क-फॉर्म-होम और हाइब्रिड वर्किंग में आपको काम के साथ बीच-बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए। आधे घंटे का ब्रेक लेकर आप खुद के काम को कर सकते हैं। इससे आपको खुद के लिए भी समय मिलता रहेगा।
- परिवार के लिए समय**
- कई बार ऑफिस का काम होने के बाद लोग अपने फोन यानी सोशल मीडिया में व्यस्त हो जाते हैं। हालांकि आपको स्क्रीन टाइम कम करने पर ध्यान देना चाहिए। बचा हुआ समय आपको परिवार को देना चाहिए या फिर आप नई चीजों को सीखने के लिए भी समय निकाल सकते हैं।
- काउंसलिंग लें**
- अगर आप इन चीजों को फॉलो करने के बाद भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल स्पेस से अलग नहीं रख पा रहे हैं तो आपको काउंसलिंग लेने की जरूरत है। काउंसलिंग की मदद से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल स्पेस में हावी नहीं होने देंगे।

नाश्ते में बनाएं राजस्थानी वड़ा गलगल का अचार और पौष्टिक चीला



गलगल का अचार

क्या चाहिए – गलगल– 2 किलो, हरी मिर्च– 250 ग्राम, अदरक– 250 ग्राम, सरसों का तेल– 200 मिली, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर– 2 बड़े चम्मच, हल्दी पाउडर– 1 बड़ा चम्मच, हींग– 1/2 छोटा चम्मच, अजवाइन– 2 बड़े चम्मच, मेथी दाना– 1 बड़ा चम्मच, काला नमक– 2 बड़े चम्मच, सादा नमक– 1 बड़ा चम्मच, शक्कर– 200 ग्राम।
ऐसे बनाएं – एक बड़े बर्तन में पानी को तेज आंच पर गर्म करें। उबाल आने पर साबुत गलगल (नींबू) डालकर 3-4 मिनट उबालें। पानी निशारकर गलगल को पोंछकर सुखा लें। इनको एक इंच के टुकड़ों में काट लें और बीज निकाल दें। हरी मिर्च को एक इंच के टुकड़ों में काटें। अदरक के भी एक इंच लंबे कतरे करें। पैन में सरसों का तेल मध्यम से तेज आंच पर गर्म करें। जब इसमें से धुआं निकलने लगे तो इसे आंच से हटा दें। तेल को दस मिनट तक ठंडा करें। इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग, अजवाइन, मेथी दाने, शक्कर और नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। फिर इसमें डालें गलगल, अदरक और हरी मिर्च। अच्छी तरह से मिलाकर जार में भरें। जार को 15-20 दिन के लिए धूप में रखें जब इसका रंग गहरा और नींबू मुलायम न हो जाए। तैयार अचार को पराठों, चीले आदि के साथ परोसें।

राजस्थानी पौष वड़ा

क्या चाहिए – चावली दाल– 1 कप, चना दाल– 1/2 कप, मूंग की धूली दाल– 1/2 कप, मेथी दाने– 2 छोटे चम्मच, साबुत धनिया– 2 छोटे चम्मच, धनिया पाउडर– 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर– 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला– 1/2 छोटा चम्मच, हींग– 1/4 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर– 1/4 छोटा चम्मच, लौंग– 4, काली मिर्च– 5, हरी मिर्च– 3 कटी हुई, अदरक– 1/2 छोटा चम्मच कटी हुई, हरा धनिया– थोड़ा-सा कटा हुआ, नमक– स्वादानुसार, तेल– तलने के लिए।
ऐसे बनाएं – सभी दालों को रातभर अलग-अलग पानी में भिगोकर रखें। फिर इन्हें निशारकर दरदरा पीस लें। दालों को पीसते समय अगर पानी कम लगे तो 1-2 बड़े चम्मच पानी डाल सकते हैं। ज्यादा पानी न डालें क्योंकि इससे घोल पतला हो जाएगा। लौंग, काली मिर्च, मेथी दाने और साबुत धनिया को भी अलग से दरदरा पीस लें। बोल में पीसी हुई दालें, पीसे हुए मसाले समेत सारी सामग्री डालें और अच्छी तरह मिलाएं। कड़ाही में तेल गर्म करें। एक-एक करके घोल के वड़े तेल में डालें। वड़ों को मध्यम आंच पर सुनहरा-भूरा और कुरकुरा होने तक तलें। चाय या हरी चटनी के साथ गर्मागर्म वड़े परोसें।

मेथी पालक चीला

क्या चाहिए – पालक– 1 कप कटी हुई, मेथी– 1/4 कप कटी हुई, हरा धनिया– 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ, पुरीना– 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ, हरी मिर्च– 1 कटी हुई, अदरक– 1/4 छोटा चम्मच कटी हुई, बेसन– 1 कप, लाल मिर्च पाउडर– 1 छोटा चम्मच, नमक– स्वादानुसार, धनिया पाउडर– 1 छोटा चम्मच, अजवाइन– 1/2 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर– 1/4 छोटा चम्मच, हींग– 1/4 छोटा चम्मच, तेल– सेकने के लिए।
ऐसे बनाएं – बोल में बेसन, पालक, मेथी, मसाले समेत सारी सामग्री डालें। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए घोल बनाएं। अब गर्म तवे पर तेल लगाएं और घोल से चीला फैलाएं। चीले पर तेल लगाते हुए दोनों तरफ से सेंकें। जब यह सुनहरा हो जाए तो इस पर कीसा हुआ पनीर और पसंदीदा चटनी लगाएं। इसे अचार के साथ भी परोस सकते हैं।

इन चार वजहों से मशीन वॉश करने के बाद कपड़ों पर नजर आते हैं सफेद दाग



कपड़े किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होते हैं। अगर हम साफ-सुथरे कपड़े पहनते हैं तो इससे हमारा फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा पड़ता है। यही कारण है कि लोग एक बार पहनने के बाद कपड़ों को मशीन वॉश करना पसंद करते हैं। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि जब आप कपड़ों को मशीन वॉश करते हैं तो अक्सर

पर गौर किया है कि मशीन में कपड़े धोने के बाद भी उनमें सफेद दाग क्यों नजर आते हैं। दरअसल, इसके पीछे कई वजहें जिम्मेदार हो सकती हैं।
पाउडर डिजेंट का इस्तेमाल करना
कपड़ों को धोने के बाद उन पर सफेद दाग नजर आने का एक मुख्य कारण पाउडर डिजेंट का उपयोग है। अक्सर पाउडर डिजेंट मशीन के पानी में उस तरह से घुलता नहीं है जैसा उसे घुलना चाहिए, जिससे कपड़ों पर धारियां पड़ जाती हैं। इसलिए, अगर आप कपड़ों पर नजर आने वाले इस सफेद दाग की समस्या से छुटकारा पाना चाहती हैं तो पाउडर डिजेंट से लिक्विड डिजेंट पर स्विच करने पर विचार करें।

डिजेंट का अधिक इस्तेमाल करना
कपड़ों का धोते समय डिजेंट की मात्रा भी बहुत मायने रखती है। कई बार लोग बेहतर सफाई के चक्कर में जरूरत से ज्यादा डिजेंट का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हालांकि, ऐसा करने से अवशेष रह सकते हैं क्योंकि यह पूरी तरह से घुल नहीं सकता या

के कारण सफेद अवशेष रह जाते हैं। ऐसे में उन कपड़ों को दोबारा धोना पड़ता है। इसलिए, आप अपनी मशीन में बहुत ज्यादा पानी न भरें, चाहे आपके पास समय की कमी क्यों न हो।
मशीन ड्रेनपाइप फ़िल्टर का बंद होना
अक्सर हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता है, लेकिन मशीन ड्रेनपाइप फ़िल्टर बंद हो जाने की स्थिति में लिंट, अघुलनशील डिजेंट और गंदगी आपके कपड़ों पर फिर से जम सकती है। इसलिए, नियमित अंतराल पर फ़िल्टर को साफ करने का नियम बनाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अधिक बेहतर साफ होते हैं।



घर खरीदना एक बहुत बड़ा निवेश है। खासतौर पर उनके लिए जिनकी आय सीमित है। अधिकांश युवाओं का मासिक वेतन 15 हजार रुपये प्रति माह से शुरू होकर लगभग 3 वर्षों में 25 से 30 हजार रुपये प्रति माह तक पहुंचता है। इसी में कई खर्चें पूरे करने होते हैं जिसके बाद घर का सपना पूरा कर पाना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। इसी वर्ग को ध्यान में रखकर हम एक ऐसी रणनीति तैयार करेंगे ताकि हर कोई अपने घर का सपना साकार कर सके।

बजट से शुरुआत

सबसे पहले अपना बजट बनाएं। इस बात का प्रयास करें कि प्रारंभ में आप ऐसा घर खरीदें, जो आपके बजट में आता हो। बाद में उसे बेचकर प्राप्त राशि को डाउन पेमेंट की तरह प्रयोग करते हुए बड़े घर के लिए बड़ा लोन लेने पर विचार कर सकते हैं।

क्षेत्र का चयन

आमतौर पर शहर के व्यस्त या विकसित इलाकों में घरों की कीमतें अधिक होती हैं। इसलिए ऐसे इलाकों की खोज करें जहां अभी कीमतें कम हैं, लेकिन अगले 5 वर्षों में बढ़ने की संभावनाएं हैं।

ऋण की पात्रता जांच लें

कोई भी बैंक घर या प्लैट की कीमत का शत-प्रतिशत लोन नहीं देता है। लोन की राशि घर की कीमत के 80 से 90 फीसदी तक हो सकती है। आपके वेतन से होने वाली कटौतियों को भी ध्यान में रखा जाता है। कुल कटौतियां 60 फीसदी से

डाउन पेमेंट

अब प्रश्न यह है कि घर की कीमत और बैंक लोन के अंतर को कैसे पाटा जाए। इस उद्देश्य से इन विकल्पों पर विचार करें-

- यदि आपके पास स्वर्ण आभूषण हैं और वो लॉकर में रखे हैं, तो उन्हें काम पर लगाएं। गोल्ड लोन आसानी से और कम ब्याज पर मिल जाता है, जिससे प्राप्त धनराशि का उपयोग आप डाउनपेमेंट अथवा मार्जिन भरने के लिए कर सकते हैं।
- पोस्ट ऑफिस के एनएससी, बीमा पॉलिसी, बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर और म्यूचुअल फंड के आधार पर भी लोन लेकर आप धन जुटा सकते हैं।



खर्चों और सीमित आय के साथ खरीदें अपने सपनों का घर

ईएमआई से पहले सिप

यदि लोन लेने के लिए आपके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है, तो कुछ वर्षों के लिए लोन लेने के विचार को स्थगित करें। ईएमआई का तनाव लेने से अच्छा है कि आप हर महीने किसी अच्छे इकटिरी म्यूचुअल फंड में एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इवेस्टमेंट की योजना बनाएं।

आवास योजना भी एक विकल्प है

यह पता लगाएं कि आपके शहर में विकास प्राधिकरण की एलआईजी और एमआईजी आय वर्ग के लिए क्या कोई आवास योजना है। प्रायः सभी बड़े शहरों में निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए आवास योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिन शहरों और कस्बों में प्राधिकरण नहीं है, वहां हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में पता करना चाहिए। अकोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत भी सस्ते घर बनाए जा रहे हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत बनाए जा रहे घरों की कीमतें काफी किफायती होती हैं।

संक्षिप्त डायरी

दहेज हत्या में फरार सास के घर कुर्की-जब्त, विवाहिता का शव गायब करने का आरोप

पटना (एअरसी) देहज के लिए विवाहिता की हत्या और शव गायब करने के मामले में मसौदी पुलिस ने फरार आरोपी सास के घर कुर्की-जब्ती की कारवांई की। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मसौदी में देहज के लिए विवाहिता की हत्या कर शव गायब करने के मामले में फरार चार रहीं। नामजद आरोपी सास के घर मसौदी पुलिस ने रविवार को कुर्की-जब्ती की कारवांई की। कारवांई जिलात बिगहा गांव स्थित आरोपी रिंकू देवी के घर पर की गयी। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पूर्व में इश्तेहा भी चिपकाया गया था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पांच लाख रुपये अतिरिक्त देहज मांगने का आरोप जहानाबाद जिले के मख्दूमपुर थाना क्षेत्र के भगवान खंडा निवासी स्व. खौरा प्रसाद की पुत्री माधुरी कुमारी (21) की शादी 11 मार्च 2024 को जिलात बिगहा निवासी सीताराम प्रसाद के पुत्र सूरज कुमार उर्फ गुट्टा (22) से हुई थी। मृतका के पिता का आरोप है कि शादी में करीब 15 लाख रुपये खर्च किये गये थे। शादी के कुछ माह बाद पति सूरज कुमार, ससुर सीताराम प्रसाद, सास रिंकू देवी, ननद कंचन कुमारी और मामा ससुर अशोक यादव पांच लाख रुपये अतिरिक्त देहज की मांग को लेकर माधुरी को प्रताड़ित करने लगे। फोन पर बतायी थी प्रताड़ना की बात परिजनों के अनुसार, इसी वर्ष 15 मई को माधुरी ने फोन कर ससुराल में प्रताड़ित किये जाने की जानकारी दी थी। इसके अगले दिन परिजन जब जिलात बिगहा स्थित उसके ससुराल पहुंचे, तो घर में ताला बंद मिला और सभी आरोपी फरार थे। परिजनों ने ग्रामीणों से पूछाछा की, तो माधुरी की हत्या कर शव गायब कर दिये जाने की जानकारी मिली। दो माह की गंभवती थी माधुरी परिजनों ने बताया कि माधुरी करीब दो माह की गंभवती थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ कारवांई शुरू की। गिरफ्तारी नहीं होने पर फरार आरोपी रिंकू देवी के घर पर कुर्की-जब्ती की गयी। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी पुलिस के अनुसार, मामले में अन्य नामजद आरोपी भी फरार हैं। उनका गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने रिंकू देवी के घर की कुर्की-जब्ती की कारवांई पूरी कर ली है।

वन देवी मंदिर में बाबा बिहटेश्वर की टीम ने की

भव्य आरती, सैकड़ों दीयों से जगमग मंदिर परिसर

पटना (एजेंसी) वन देवी मंदिर में बाबा बिहटेश्वर नाथ आरती टीम ने सैकड़ों दीयों की रोशनी और भजन-कीर्तन के साथ भव्य आरती का आयोजन किया। आस्था और प्रकाश का अद्भुत संगम, बाबा बिहटेश्वर नाथ भक्ति की आरती टीम की ओर से वन देवी मंदिर में भजन-कीर्तन और मंत्रों आरती का आयोजन किया गया, पुजारी हरिओम जी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में माता का विधि-विधान से भव्य श्रृंगार किया गया। इसके बाद भजन-कीर्तन और आरती का आयोजन हुआ। सैकड़ों दीयों से जगमगाती वन देवी मंदिर दीपोत्सव के दौरान मंदिर परिसर में सैकड़ों दीप जलाये गये, दीपों की रोशनी से पूरा मंदिर परिसर जगमगा उठा, मंदिर के आकर्षक स्वरूप को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, श्रद्धालुओं ने कहा कि वन देवी मंदिर में पहली बार इस तरह का भव्य दीपोत्सव देखने को मिला, भजन-कीर्तन से भक्तिमय हुआ माहौल कार्यक्रम का संचालन पुजारी हरिओम जी के नेतृत्व में किया गया, भोला जी के नेतृत्व में भजन-कीर्तन प्रस्तुत किया गया, भजनों के बाद श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भव्य आरती हुई, दीपों की रोशनी, भजन और आरती से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। आस्था और रोशनी का दिख्ख अद्भुत संगम दीपोत्सव के दौरान मंदिर परिसर में सैकड़ों दीपों का आकर्षक नजारा देखने को मिला, श्रद्धालु भक्ति और आस्था में लीन नजर आए, पूरे कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में उत्साह और भक्तिमय माहौल बना रहा।

**पटना में प्रदर्शन: वाटर कैनन चलते ही नाचने लगे
प्रदर्शनकारी, बैरिकेड्स उड़ाकर फेंकने की कोशिश**

पटना (एजेंसी) पटना में किसानों, छात्रों और मजदूरों के प्रदर्शन के दौरान हंगामा, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश, कई लोग हिरासत में लिए गए। स्वास्थ्य विगड़ने की भी खबरें। पटना में सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों के सड़कों पर उतरने से कई इलाकों में हचलचल बढ़ गई। गांधी मैदान से आक्रोशित लोगों ने मार्च निकाला था, जो जेपी गौलबरगर पहुँचे होते हुए डाकबंगला चौराहे तक पहुंचा। प्रदर्शन को देखते हुए पटना पुलिस ने कई प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर बहस और झड़प की स्थिति भी बनी। इस दौरान प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़ उठाकर फेंकने की कोशिश करते नजर आए। वाटर कैनन चलते ही भीड़ नष्ट होने लगे प्रदर्शनकारी इसी बीच पटना के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के



लिए वाटर कैनन चलाया. पानी की बौछार पड़ते ही कुछ प्रदर्शनकारी नाचते नजर आए. उन्होंने पुलिस को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इतनी गर्मी में वाटर कैनन चलाकर उन्हें राहत मिल रही है. रज्ज कृतिका मिश्रा ने किया अनाउंसमेंट वाटर कैनन के बीच पटना सदर रज्ज कृतिका मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों से धैर्य रखने की अपील की. उन्होंने अनाउंस करते हुए कहा कि



प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत हो चुकी है। जल्द ही उन्हें उचित मंच पर बातचीत के लिए ले जाया जाएगा। रूट ने प्रदर्शनकारियों से शांत रहने और धैर्य बनाए रखने की अपील की। गांधी मैदान से निकला आक्रोश मार्च जानकारी के अनुसार, गांधी मैदान के गेट नंबर-10 से आक्रोश मार्च निकाला गया। इसमें किसान, छात्र-नौजवान, मजदूरों के साथ अकस्म्र उदक

पटना: गंगा में नहाने के दौरान चार दोस्त डूबे, तीन को बचाकर खुद तेज धारा में बहकर लापता हो गया आशुतोष

पटना (एजेंसी) पटना के मेर में गंगा नदी में नहाने के दौरान 4 दोस्त डूब गए. आशुतोष ने बचानी की परवाह किए बिना 3 दोस्तों को जाना गया, लेकिन खुद लापता हो गया. राजधानी पटना के मेर थाना क्षेत्र के खासपुर के पास रविवार को गंगा नदी में नहाने के दौरान चार युवक डूबने लगे. इस दौरान एक युवक ने अपनी जान की परवाह किये बिना तीन दोस्तों को बचा लिया, लेकिन उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के दौरान वह खुद थककर गंगा की तेज धारा में डूब गया और लापता हो गया.



बचानो खुद दुबा तीनो दोस्तों को बचाने के बाद आशुतोष काफी थक गया। इसी दौरान गंगा की तेज धारा की चपेट में आने से वह खुद डूब गया और लापता हो गया। आशुतोष के नदी में डूबने की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। इसके बाद परिवार में चीख-पुकार मच गयी। स्थानीय गोताखोरों ने शुरू की तलाश-बोधा गटना की सूचना मुखिया प्रतिनिधि बोधनाथ

राय ने तत्काल प्रशासन को दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और युवक को तलाश शुरू करावी. दोर शाम तक एसडीआरएफ की टीम के नहीं पहुंचने पर स्थानीय गोटलाखोरों की मदद से गंगा में तलाशी अभियान चलाया गया. हालांकि, काफ़ी प्रयास के बावजूद दोर शाम तक आशुतोष को कोड़े पता नहीं चल सका था.



क्यों पड़ी? अक्सर यह देखा जाता है। यह
 कि सरकार को तुरफ से कर
 कल्याणकारी योजनाएँ और नीतियाँ लागू
 लागू की जाती हैं, लेकिन सही समयवश
 पर सही जानकारी न मिलने के
 कारण आम लोग उनका लाभ उठाने में
 से वंचित रह जाते हैं। इसके कारण
 अलावा, किसी योजना पर कठिनता से
 काम हुआ है, इसका सटीक डेटा भी
 जनाता तक आसानी से नहीं पहुँचता
 पाता था। इसी समस्या के समाधान के
 के लिए 'संकल्प पोर्टल' को
 विकसित किया जा रहा है। यह एक
 एकीकृत (इंटीग्रेटेड) डिजिटल

लेटरफॉर्म होगा, जहाँ बिहार सरकारका विचार के सभी विषयों द्वारा लिए गए फैसलों, घोषित संकल्पों, और चल रही परियोजनाओं की अद्यतनता (अपडेटेड) जानकारी दर्ज की जाएगी। इस पोर्टल के शुरू होने से आम नागरिकों को एक ही जगह पर प्रामाणिक जानकारी मिलेगी। पोर्टल की मुख्य विशेषताएं और 10 देशबोर्ड विडो संकल्प पोर्टल की उपयोगकर्ताओं की सुविधा के अनुसार कारी सल और इंटीक्विटी बनाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, इस पोर्टल के देशबोर्ड पर

कान में मवाद और दर्द का इलाज अब जांच के बाद, पटना एम्स जारी करेगा नई गाइडलाइन



असर कम हो रहा है। सामान्य एंटीबायोटिक के प्रति बढ़ रही प्रतिरोधक क्षमता केस स्टडी में पाया गया कि सीएसओएम के इलाज में लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही कुछ सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति बैक्टीरिया की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। ऐसे में बिना जांच

के अनुमान के आधार पर एंटीबायोटिक देना प्रभावी नहीं मानना जा रहा है। एम्स पटना के निदेशक डॉ. राजू अग्रवाल ने कहा कि एंटीबायोटिक दवा कब और किसस्य मरीज को देनी है, इसे लेकर संस्थान के चिकित्सकों की ओर से लगातार रिसर्च की जा रही है। उन्होंने कहा

कि कान-नाक-गला से संबंधित मरीजों के इलाज से पहले एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी और बैक्टीरियल कल्चर जांच कराना जरूरी है, ताकि संक्रमण के लिए उपयुक्त दवा का चयन किया जा सके। बैक्टीरियल कल्चर के बाद ही तय होगी दवा एम्स पटना के डॉक्टर

के अनुसार, कान से लंबे समय तक मवाद बहने वाले मरीजों में कुछ एंटीबायोटिक दवाएं गंभीर संक्रमण के मामलों में प्रभावी पायी गयी हैं। पाइपरसिलिन-टैजोबैक्मिक, इमीपेनम मेरोपेनम और एमिकासिन जैसे दवाएं कई मामलों में अस्पर्दा पायी गयी हैं। वहीं, जेटाबैक्मिन जैसी कुछ दवाओं के खिलाफ बैक्टीरिया का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने की बात सामने आयी है। डॉक्टरों का कहना है कि इन दवाओं का इस्तेमाल बिना चिकित्सकीय सलाह के नहीं किया जाना चाहिए। सीएसओएम के मरीजों में सेंसिटिविटी और बैक्टीरियाएं कल्चर जांच के बाद ही एंटीबायोटिक का चयन किया जाना चाहिए, इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि संबंधित संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया पर कौन सा दवा अधिक प्रभावी हो सकती है। सेंसिटिविटी जांच क्यों है जरूरी

सटीक बैक्टीरिया की पहचान: कान के संक्रमण कई तरह के बैक्टीरिया के कारण हो सकते हैं. क्लचर और स्ट्रॉफोकोकस बैक्टीरिया के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया की पहचान करने में मदद मिलती है. सही दवा का चुनाव: कई बार सामान्य एंटीबायोटिक दवाएं संक्रमण पर प्रभावी नहीं होती हैं. सेंसिटिविटी टेस्ट्स से डॉक्टरों को यह पता करने में मदद मिलती है कि संबंधित बैक्टीरिया पर कौन सी एंटीबायोटिक प्रभावी हो सकती है. साइड इफेक्ट और सुनने की क्षमता की सुरक्षा: कुछ शक्तिशाली एंटीबायोटिक, विशेषकर एमिनोग्लाइकोसाइड वर्ग की दवाओं के अनुचित इस्तेमाल से कान के नुकसान पहुंचने का जोखिम हो सकता है. जांच के आधार पर दवा का चयन करने से अनावश्यक एंटीबायोटिक इस्तेमाल को कम करने में मदद मिल सकती है.

**पटना में 330 करोड़ से बनेगी 6.8 किमी लंबी
फोरलेन सड़क, 1.57 एकड़ जमीन का होगा**



नानाया जायेगा. सड़क की चौड़ाई 14 मीटर होगी. चौड़ी सड़क बनने से इस मार्ग पर वाहनों के आवागमन के लिए अधिक जगह उपलब्ध होगी और मौजूदा सड़क की क्षमता बढ़ेगी. निर्माण पर खर्च होगा 330.24 करोड़ रुपये परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण और इससे जुड़े निर्माण कार्यों पर 330.24 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे. सड़क निर्माण के साथ माफा पुल-पुलिया का भी निर्माण किया जायेगा, इससे सड़क के विभिन्न हिस्सों में आवागमन को बेहतर बनाने में मदद

मिलेगी. फोरलेन बनने के बाद इस मार्ग की यातायात क्षमता बढ़ने की उम्मीद है. पांच लाख आबादी के आवगमन में मिलेगी सुविधा परसा संपतचक सड़क के चौड़ीकरण करीब पांच लाख की आबादी के आवगमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है. इस मार्ग का उपयोग करने वाले लोगों को चौड़ी सड़क का लाभ मिलेगा. खासकर परसा और संपतचक के बीच आने-जाने वाला वहनों के लिए सड़क की क्षमता बढ़ने से आवगमन आसान हो सकता है.

**बच्चों में गुर्दे की बीमारी के ये लक्षण दिखें तो न करें
नजरअंदाज, पटना में विशेषज्ञों ने बतायी जरूरी बातें**



विशेषज्ञों ने बच्चों की बीमारियों की शुरुआती पहचान और उचित इलाज के महत्व पर भी चर्चा की. होटल चाणक्या में हुआ विशेष आयोजन पटना के आर ब्लॉक स्थित होटल चाणक्या में बच्चों के समुचित विकास और पोषण प्रबंधन को लेकर विशेष वर्कशॉप आयोजित किया गया. कार्यक्रम में बाल स्वास्थ्य से

जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। पीएमसीएफ के डॉक्टरों ने किया उद्घाटन कार्यक्रम का उद्घाटन पीएमसीएफ के डॉ मैथिली सिन्हा, डॉ पंकज हंस, डॉ संतोष कुमार और स्मृति रंजन पंडित ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। बच्चों में गुद की बीमारियाँ पर क्या रोग विशेषज्ञ डॉ पंकज हंस ने बच्चों में गुद से जुड़ी बीमारियों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभिभावकों की जागरूकता की कमी के कारण बच्चों में गुद संबंधी बीमारियों की पहचान में देर

हो सकती है। सूजन और पेशाब का बदलाव हो सकते हैं। संकेत डॉक्टरों को सूझा सकते हैं कि आपको सूजन हो रही है। सूजन, पेशाब में जलन या पेशाब में खून आना गुंठे से जुड़ी समस्या के संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर बच्चों को चिकित्सकीय जांच कराना जरूरी है। बच्चों में किडनी बीमारी को लेकर धबधबे की जरूरत नहीं विशेषज्ञ ने बताया कि बच्चों में गुंठे से जुड़ी बीमारी को लेकर धबधबे की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चों में यह बीमारी लाइलाज नहीं है और समय पर बीमारी की पहचान और उचित उपचार महत्वपूर्ण है।

डीआरडीओ का हल्के ‘बुलेटप्रूफ’ कांच के लिए सीजीसीआरआई से समझौता

50 करोड़ की परियोजना, बख्तरबंद वाहनों के लिए आयात विकल्प

कोलकाता ।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने बख्तरबंद वाहनों के लिए स्वदेशी, उन्नत एवं हल्के बुलेटप्रूफ कांच के विकास हेतु सीएसआईआर-केंद्रीय कांच एवं सिरैमिक अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीजीसीआरआई) के साथ 50 करोड़ रुपये की एक बड़ी परियोजना के लिए हाथ मिलाया है। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य आयातित पारदर्शी कवच का प्रभावी विकल्प तैयार करना और उसके वजन तथा मोटाई को मौजूदा स्तर से 50 प्रतिशत तक कम करना है। चार साल की यह परियोजना वर्तमान में उन्नत चरण में है। इसमें महाराष्ट्र स्थित नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएमआरएल) और चंडीगढ़ स्थित टीबीआरएल सहित डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाएं भी सहयोग कर रही हैं। परियोजना का अगला चरण प्रयोगशाला स्तर के विकास से बड़े पैमाने पर विनिर्माण तक प्रौद्योगिकी को ले जाने के लिए डीआरडीओ द्वारा चुने गए उद्योग साझेदार के साथ काम करना होगा। सीएसआईआर-सीजीसीआरआई के एक वे रिष्ठ अे अधिकारी ने बताया कि यह परियोजना रक्षा क्षेत्र के लिए उन्नत स्वदेशी बुलेटप्रूफ कांच प्रौद्योगिकी विकसित करेगी, जो भारत की रणनीतिक जरूरतों को सीधे संबोधित करती है। कोलकाता स्थित संस्थान के अधिकारियों ने पुष्टि की कि लक्ष्य ऐसे उन्नत आर्मी ग्लास-सिरैमिक विकसित करना है, जो पारंपरिक कवच की तुलना में काफी हल्के और पतले होने के साथ-साथ कई गोणियों से सुरक्षा प्रदान कर सकें।

गोदरेज प्रॉपर्टीज का मुंबई में 6000 करोड़ का मेगा-प्लान!

दक्षिण मुंबई के महीन लाइसें में 2.5 एकड़ भूमि पर विकसित होगी प्रीमियम आवासीय परियोजना

मुंबई ।

रियल एस्टेट सेक्टर की अग्रणी कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड (जीपीएल) ने अपनी विस्तार योजनाओं को गति देते हुए मुंबई के प्रमुख लक्जरी रियल एस्टेट बाजार में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने दक्षिण मुंबई के मरीन लाइंस में 2.5 एकड़ में एक प्रीमियम आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए एक समझौते की घोषणा की है, जिससे उसे अनुमानित 6,000 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजार को बताया कि यह परियोजना संयुक्त रूप से विकसित की जाएगी और यह उसके पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। जीपीएल के एक प्रमुख अे अधिकारी ने मुंबई को कंपनी के लिए एक प्रमुख बाजार बताया, जहां प्रीमियम और लक्जरी परियोजनाओं को लगातार मजबूत प्रतिक्रिया मिली है। यह विकास ऐसे समय में आया है जब मुंबई का लक्जरी आवास बाजार मजबूती से बढ़ रहा है। संपत्ति सलाहकार इंडिया सोथबीज इंटरनेशनल रियल्टी और सीआई मैट्रिक्स के अनुसार, इस साल की पहली छमाही में 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक कीमत वाले लक्जरी मकानों की बिक्री 12 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 18,512 करोड़ रुपये हो गई है।

कटाई से पहले धान की फसल पर मौसम की मार, किसानों को दोहरी चिंता

दयालपुर में तैयार खड़ी फसल खेतों में बिछी, किसान पैदावार पटने और मंडी में रेट कम मिलने से परेशान

फरीदाबाद ।

फरीदाबाद के दयालपुर गांव में पिछले दिनों हुई भारी बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की तैयार खड़ी धान की फसल को खेतों में बिछा दिया है।

कटाई से महज 10-15 दिन पहले हुए इस नुकसान से किसान गहरे सदमे में हैं और उन्हें पैदावार में कमी तथा मंडी में फसल का सही दाम न मिलने की दोहरी चिंता सता रही है। किसानों का कहना है कि साल की शुरुआत में गेहूं की फसल को भी आखिरी दौर में मौसम की मार झेलनी पड़ी थी, और अब धान के साथ भी ऐसी ही स्थिति सामने आई है। दयालपुर गांव के एक किसान ने कहा कि रात में तेज बारिश के साथ आंधी चलने से उनकी 4 एकड़ में लगी 1509 किस्म की धान की फसल पूरी तरह खेत में बिछ गई है। वे करीब 40 प्रतिशत नुकसान का अनुमान लगा रहे हैं। धान की खेती में प्रति एकड़ लाभग 20 हजार रुपये की लागत आती है और फसल लगभग पककर तैयार थी। यदि 15 से 20 दिन और मौसम ठीक रहता तो धान की कटाई कर उसे मंडी पहुंचाया जा सकता था। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खेत में नीचे गिरे दाने ठीक से नहीं पाएंगे और कुछ दाने भी पड़ सकते हैं। इससे न केवल पैदावार कम होगी, बल्कि मंडी में उचित रेट भी नहीं मिल पाएगा।

स्टॉक मार्केट में यूपीआई भुगतान पर नया एमडीआर, ब्रोकरों पर पड़ेगा बोझ

एनएसई ने सरकार से बातचीत की खबरों को नकारा, ब्रोकरों की बड़ी चिंता

नई दिल्ली ।

भारतीय शेयर बाजार में यूपीआई के माध्यम से होने वाले भुगतानों पर अब नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होगा। 15 अक्टूबर से प्रभावी होने वाला यह नियम शेयर, स्विफोरटीज, म्यूचुअल फंड और स्टॉक ब्रोकर से जुड़े लेनदेन पर 0.02 फीसदी एमडीआर लगाएगा,

जिसकी अधिकतम सीमा प्रति लेनदेन 300 रुपये होगी। यह शुल्क सीधे ग्राहक से न लेकर भुगतान प्राप्त करने वाले ब्रोकरों और संबंधित कंपनियों पर लागत का बोझ डालेगा। यह एमडीआर भुगतान प्राप्त करने वाले मर्चेंट या ब्रोकर की लागत होती है, जिससे ब्रोकरों के सामने एक अतिरिक्त लागत का सवाल खड़ा हो गया है। विशेष रूप से तब, जब कोई

ग्राहक यूपीआई के जरिए पैसे जमा करता है, लेकिन बाद में उन पैसें से कोई शेयर नहीं खरीदता, ऐसी स्थिति में भी ब्रोकर को एमडीआर का खर्च उठाना पड़ सकता है। हालांकि, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के एक प्रमुख अे अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि एमडीआर को लेकर उनकी सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है। उनके अनुसार इस नए शुल्क



का व्यावहारिक समाधान ब्रोकर और ग्राहकों को मिलकर निकालना होगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नियम बाजार प्रतिभागियों और ग्राहकों को किस तरह प्रभावित करता है।

तत्काल पैसों की जरूरत? एफडी तोड़ने से बेहतर है उस पर लोन लेना

नई दिल्ली ।

अचानक वित्तीय जरूरत पड़ने पर फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) मालिकों के सामने एफडी तोड़ने या उसके बदले लोन लेने का विकल्प होता है। वित्तीय विशेषज्ञ एफडी को बरकरार रखते हुए उस

पर लोन लेने को एक स्मार्ट वित्तीय निर्णय मानते हैं, जिससे आप पेनल्टी और ब्याज के नुकसान से बचेते हैं। अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर फिक्स्ड डिपॉजिट के मालिक अक्सर दुविधा में होते हैं कि इसे तोड़ें या इसके बदले लोन लें।

वित्तीय विशेषज्ञ मानते हैं कि एफडी तोड़ने से होने वाले नुकसान से बचने के लिए उस पर लोन लेना एक समझदारी भरा विकल्प है। मान लीजिए आपको 3 लाख रुपये चाहिए और आपके पास 5 लाख रुपये की 7 फीसदी ब्याज वाली एक साल की एफडी

है। यदि आप 6 महीने बाद एफडी तोड़ते हैं, तो बैंक पेनल्टी के साथ ब्याज दर घटाकर 5 फीसदी प्रभावी कर सकता है, जिससे आपको लगभग 12,500 रुपये ब्याज मिलेंगे। यह पूर्ण अवधि के 35,000 रुपये के संभावित ब्याज से काफी कम है।

शेयर बाजार में हाहाकार ! सेंसेक्स 1000 अंक टूटा, निफ्टी 23000 पर

चंद्र मिनटों में ही निवेशकों के 4.3 लाख करोड़ डूबे मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को शुरुआती कारोबार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बुरी तरह गिरे। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं बाजार पर छावीं रहीं। एशियाई बाजारों में कमजोर रख ने भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। विदेशी पूंजी की निकासी ने भी शुरुआती कारोबार के दौरान निवेशकों के मनोबल को चोट पहुंचाई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआती

कारोबार में 730 अंक गिरकर 73,170.12 पर आ गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 231.50 अंक टूटकर 22,908.95 पर पहुंच गया। सुबह 10 बजकर 45 मिनट पर सेंसेक्स 1,010.46 अंकों की गिरावट के साथ 72,885.28 के स्तर पर जबकि निफ्टी 309.66 अंकों की गिरावट के साथ 22,830.85 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। इस बड़ी गिरावट के चलते निवेशकों को चंद्र मिनटों में ही लगभग 4.3 लाख करोड़ रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ा। बाजार ट्रंप और कच्चे तेल का खेल बाजार में इस तीव्र गिरावट की मुख्य वजह अमेरिकी राष्ट्रपति



डोनाल्ड ट्रंप का ईशान के साथ हुए सात-दिवसीय समझौते को अस्वीकार करना है। ईरान ने अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाने के बदले महत्वपूर्ण शिपिंग रूट होर्मुज जलडमरूमध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए खोलने का प्रस्ताव रखा था, जिसे

ट्रंप ने ठुकरा दिया। इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़ गईं। इस गिरावट के अन्य कारणों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली और अमेरिकी ब्याज दरों का दबाव भी शामिल है।

अमेरिका से भारत को राहत, एल्युमिनियम कैन स्टॉक पर आंशिक शुल्क हटे

वॉशिंगटन ।

वाणिज्य विभाग ने भारत समेत कई देशों से आयात होने वाले कुछ खास एल्युमिनियम कैन स्टॉक पर लागू एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी से आंशिक रूप से पाबंदियां हटा दी हैं। विभाग ने बदले हुए हालात की अपनी समीक्षा के अंतिम नतीजों की घोषणा की, जिसके तहत यह फैसला 24 सितंबर से लागू माना जाएगा। यह कदम भारतीय एल्युमिनियम निर्यातकों के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे अमेरिकी बाजार में उनकी पहुंच आसान होगी। यह आंशिक छूट उन एल्युमिनियम स्टॉक पर लागू होगी जो विशेष रूप से पेय पदार्थों के कैन, कैन के ढक्कन और कैन खोलने के लिए इस्तेमाल होने वाले टैब बनाने के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि, इसका यह मतलब

नहीं है कि सभी कॉमन अलॉय एल्युमिनियम शीट पर लगे व्यापारिक शुल्क खत्म कर दिए गए हैं; व्यापक एंटी-डंपिंग और अन्य व्यापारिक शुल्क अभी भी लागू रहेंगे। उत्पाद की पात्रता उसके लिखित तकनीकी विवरण के आधार पर तय की जाएगी, न कि अमेरिकी टैरिफ सिस्टम में उसकी कैटेगरी के आधार पर। यह फैसला भारत के आलावा बहरीन, ब्राजील, क्रोएशिया, मिश्र, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, ओमान, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, ताइवान और तुर्की से आने वाली एल्युमिनियम शीट से जुड़े मौजूदा आदेशों पर भी असर डालेगा। चीन से आयात होने वाली एल्युमिनियम शीट पर भी अलग से असर होगा। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने यह समीक्षा तब शुरू की थी जब अमेरिका की एल्युमिनियम इंडस्ट्री



के कुछ सदस्यों ने कैन बनाने में इस्तेमाल होने वाले एल्युमिनियम स्टॉक को मिलने वाली छूट के नियमों को स्पष्ट करने की मांग की थी। इंडस्ट्री ने तर्क दिया था कि तय शर्तों को पूरा करने वाले एल्युमिनियम कैन स्टॉक को हमेशा से इन व्यापारिक शुल्कों के दायरे से बाहर रखने का इरादा था। यह राहत न केवल भविष्य के आयात पर लागू होगी, बल्कि उन पुराने योग्य आयातों पर भी लागू होगी जिन पर अमेरिकी कस्टम

अधिकारियों ने अभी अंतिम रूप से शुल्क तय नहीं किया है। वाणिज्य विभाग के मुताबिक, आंशिक छूट उस तरीक़ से लागू होगी जब इन सामानों की अंतिम कस्टम प्रक्रिया को रोकना शुरू किया गया था।

यह भारत जैसे एल्युमिनियम उत्पादकों और निर्यातकों के लिए एक सकारात्मक विकास है, जिनके उत्पाद अमेरिका के मेटल आयात से जुड़ी व्यापार नीतियों से प्रभावित होते रहे हैं।

1 अक्टूबर से एलपीजी सब्सिडी के लिए बायोमैट्रिक आधार सत्यापन अनिवार्य

बिना ई-केवाईसी या बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन के नहीं मिलेगी सब्सिडी नई दिल्ली ।

1 अक्टूबर से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए सब्सिडी के नियमों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अब सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए बायोमैट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (बीएए) को अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही, दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपये पर स्थिर बनी हुई है। मंत्रालय के नए नियम के अनुसार जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी या बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं किया है, उन्हें 1 अक्टूबर से मिलने वाली सरकारी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। हालांकि, आपका गैस कनेक्शन चालू रहेगा और सिलेंडर की डिलीवरी भी होती रहेगी, लेकिन आपको सब्सिडी वाले रेट पर नहीं, बल्कि बाजार भाव पर सिलेंडर खरीदना होगा।

फिलहाल, 28 सितंबर को दिल्ली में 14.2 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 942 रुपये और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2747.50 रुपये में बिक रहा है, जो पहले के स्तर पर बरकरार है। वहीं दूसरी ओर एशियाई बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 1 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

पेज एक का शेप

प्रहार को थाना स्तर तक पहुंचाएं...

उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए विशेष टीम गठित करने को कहा। शाह के अनुसार, सरकार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लेकर आई है। उन्होंने कहा कि एजेंसियों के बेहतर समन्वय के परिणामस्वरूप सीमापार हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल शहजदा भट्ठी नेटवर्क के 40 से अधिक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया तथा 15 राज्यों में 100 से अधिक प्राथमिकी दर्ज कर 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया। समेलन में केंद्रीय गृह सचिव, विदेश सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख, 15 राज्यों के मुख्य महानिदेशक तथा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आतंकवाद-रोधी दस्तों के प्रमुख शामिल हुए। अन्य राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया।

नाबालिगों के मामले में सोशल मीडिया...

एच.एस. फुल्का ने कहा कि केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल मध्यस्थों को भारतीय कानूनों का पालन करने के निर्देश दे सकता है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों को इस बात का ध्यान रखने के निर्देश दिए जाएं कि नाबालिगों में अनुबंध करने की कानूनी क्षमता नहीं होती और ऑनलाइन सेवाओं तक उनकी पहुंच के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं। एच.एस. फुल्का ने कहा, हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भारत के कानूनों का उल्लंघन करने से रोकें जाएं। याचिका में ऑनलाइन दुनिया में बच्चों के सामने मौजूद कई खिखिमां को भी उठाया गया है। इनमें बच्चों को बहला-फुसलाकर यौन शोषण की ओर ले जाना, यौन शोषण, ऑनलाइन ट्रैफिकिंग, सेक्सटॉर्शन, बच्चों के व्यवहार की प्रोफाइलिंग, निजी डेटा का दुरुपयोग और साइबर बुलिंग जैसी चिंताएं शामिल हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जस्ट राइट्स फॉर विल्डने के संस्थापक भुवन ऋषु ने कहा, यह तथ्य है कि बच्चों को किसी तरह का अनुबंध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और सोशल मीडिया कंपनियों के साथ उनके द्वारा किए गए ऐसे सभी समझौते अमान्य हैं। यह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। दुनिया भर में कानूनों को समझने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है, ताकि ब्याज सुनिश्चित हो और बच्चों की सुरक्षा की जा सके। जब उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी देना और अपनी पहचान उजागर करना अनिवार्य किया जाएगा, तो इससे बच्चों के ऑनलाइन शोषण और उनके साथ होने वाले दुर्यवहार में काफी कमी आएगी।

